नोएडा में जेपी इंफ्रा के 'घोस्ट टाउन' में काम शुरू होने से 20,000 घर खरीदारों के लिए आशा की किरण

लगभग 20,000 जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के घर खरीदारों के लिए, जो 13 वर्षों से अधिक समय से अपने फ्लैटों के हैंडओवर का इंतजार कर रहे हैं, आशा की एक किरण उभरी है क्योंकि पूर्ववर्ती 'घोस्ट टाउन' में कम से कम 59 अधूरे टावरों पर काम शुरू हो गया है। जल्दी करो।

इस साल मार्च में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को खरीदने और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फैली विभिन्न रुकी हुई परियोजनाओं में आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए मुंबई स्थित सुरक्षा समूह की बोली को मंजूरी दे दी।

सुरक्षा कर्ज में डूबी जेपी समूह की कंपनी में 250 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, साथ ही अगले चार वर्षों में फ्लैटों को पूरा करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का ऋण भी दे रही है।

जयश्री स्वामीनाथन, एक घर खरीदार जिसने अपनी आंखों के सामने एक दशक पुरानी पीड़ा देखी है, उसे राहत है कि अधिकांश खरीदारों के लिए इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा।

"जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) अभी भी तुच्छ अपील कर रही है और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) के अधिकारियों ने मुआवजे के मुद्दों और अन्य भूमि बकाया को सुलझाने के लिए सुरक्षा समूह से मुलाकात की है, घर खरीदार उत्साहित हैं कि कई अधूरे टावरों पर काम अब प्रगति पर है , “स्वामीनाथन ने आईएएनएस को बताया।

"एनसीएलटी के फैसले के बाद, सुरक्षा को कानूनी आधार पर YEIDA को एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी, वे किसानों को लगभग 1,689 करोड़ रुपये का मुआवजा देने को तैयार हैं, जिसका अधिकारियों को संज्ञान लेना होगा और गति बढ़ानी होगी लंबित फ्लैटों को यथाशीघ्र वितरित करने के लिए, “उसने कहा।

YEIDA जेपी इंफ्राटेक या टेकओवर कंपनी सुरक्षा से 64.7 फीसदी बढ़े हुए भूमि मुआवजे के रूप में 1,689 करोड़ रुपये और अतिरिक्त भूमि मुआवजे के रूप में 6,111 करोड़ रुपये की वसूली करना चाहता है।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए, YEIDA ने NCLT के आदेश को NCLAT में चुनौती दी, जिसमें दोनों हितधारकों को बैठकों के माध्यम से मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया गया था।

सुरक्षा समूह ने हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ लगभग 20,000 फ्लैट बनाने और किसानों को मुआवजा देने पर सहमति व्यक्त की गई है।

अगस्त 2017 में, एनसीएलटी ने नोएडा स्थित रियल्टी प्रमुख के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू की।

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया था, 18,767 सक्रिय घर खरीदार थे जिन्होंने 8,676 करोड़ रुपये की सामूहिक मूल राशि का भुगतान किया था। लगभग 413 घर खरीदारों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी और उनका 64 करोड़ रुपये का रिफंड अभी भी लंबित है।

लगभग 1,410 खरीदारों को 528 करोड़ रुपये मूल्य के कब्जे के प्रस्ताव जारी किए गए, लेकिन कोई पंजीकरण नहीं हुआ।

अपनी बेटी को नजदीकी लॉ स्कूल में पढ़ाने की उम्मीद में, स्वामीनाथन ने 2009 में केंसिंग्टन पार्क हाइट्स - एक जेपी संपत्ति - में 2,100 वर्ग फुट का अपार्टमेंट बुक किया।

"मैं अपने माता-पिता, विशेष रूप से अपनी मां की, हमारे ही घर में एक साथ रहने की इच्छा को पूरा नहीं कर सका। मैं अभी भी दिल्ली में किराए पर रह रहा हूं। इस संपत्ति को खरीदने का पूरा उद्देश्य खो गया है जिसके लिए हमने अपनी नाक से भुगतान किया था। हमने स्वामीनाथन ने आईएएनएस को बताया, "कानूनी लड़ाई से बेहद थक गए हैं।"

ऐसे कई निराश जेपी खरीदार हैं जिन्होंने ईएमआई का भुगतान करना बंद कर दिया है, क्योंकि वे किराया और ईएमआई दोनों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे।

कई सेना अधिकारियों ने जेपी विश टाउन और अन्य संपत्तियों में फ्लैट बुक करने के लिए अपना पूरा सेवानिवृत्ति लाभ खर्च कर दिया और अभी भी किराए के परिसर में रह रहे हैं।

स्वामीनाथन ने कहा, "मेरा दिल उन लोगों के लिए दुख है जिन्होंने सभी उम्मीदें खो दीं, उनके परिवार के सदस्यों की पिछले दशक में मृत्यु हो गई, क्योंकि वे अपने फ्लैटों का इंतजार कर रहे थे। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, और मेरी भी।"